भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून / Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

**पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/135/2025/एफ.सी.** **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

**प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी**
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषयः जनपद - चमोली के अन्तर्गत कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.459 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.-FP/UK/ROAD/145990/2021).**

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 834/12-1: देहारादून: दिनांक 17.10.2025 (received online on 21.01.2026).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति मांगी थी। उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी हैं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः-

1. The muck dumping yard has not been demarcated in the KML file. The same shall be clearly delineated and submitted.
2. The proposed diversion area is reported as 6.459 ha, whereas the DSS-calculated area is 6.38 ha (including Naap land). Therefore, a revised KML file reflecting the correct forest land area of 6.459 ha including muck dumping sites shall be submitted.
3. The Geologist's report prepared in 2010. A revised and updated Geologist's report, assessing the current site conditions and suitability of the area for road construction is required.
4. The Administrative Approval was issued in the year 2009. A revised Administrative Approval of the current year shall be submitted.

5. As per Part-I, the project cost is indicated as ₹486 lakh, whereas the Administrative Approval reflects ₹810.98 lakh. The discrepancy shall be clearly justified and reconciled by the User Agency.
6. It is observed that most of the submitted documents are outdated (prior to 2020 or more). The Divisional Forest Officer (DFO) and the User Agency shall review and update all relevant documents in accordance with the present scenario and resubmit the same.
7. Large numbers of trees are proposed for felling. The DFO concerned along with the user agency shall identify the status of trees in current scenario any possibility to reduce the same.
8. Muck Dumping proposed in Forest land. Whether this area is included in the proposed diversion area (of 6.459 ha) or not. The user agency shall clarify the same.
9. How many trees are falling in Muck Dumping location? Detailed information regarding the same shall be submitted by the user agency.
10. Cost-Benefit analysis of project is required to submit.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Digitally signed by Neelima Shah
Date: 24-03-2026 16:09:58

**(नीलिमा शाह, भा०व०से०)**
**सहायक महानिरीक्षक वन** (**केन्द्रीय**)

**प्रतिलिपि:-** प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।